

from sales-tax would be augmented by about five times more if they are replaced by the additional excise duty and, if so, are the Government proposing to take any steps thereon?

**Shri T. T. Krishnamachari:** The matter was generally discussed, as I said. Whether the income will be augmented or not depends upon the nature of the steps that are taken. It would be rather premature for me to discuss the matter at this stage.

**Ch. Ranbir Singh:** May I know whether the Conference considered the replacement of the outmoded land revenue system by some progressive taxation policy?

**Mr. Deputy-Speaker:** Sales-tax is sought to be removed in lieu of certain additional excises. Next question.

**Shri B. R. Bhagat:** I am sorry it is a long answer in Hindi.

**Mr. Deputy-Speaker:** If he has prepared it, he might read it.

अफीम फैक्टरी, गाजीपुर

\*६१४. श्री सरजू पाण्डे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजीपुर जिले की अफीम फैक्टरी के पास कितनी एकड़ भूमि है ;

(ख) क्या यह सच है कि पोलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इंस्टीट्यूट के विस्तार के लिए भूमि देने के सम्बन्ध में प्रार्थना की थी ;

(ग) यदि हाँ, तो कितनी एकड़ भूमि की मांग की गयी थी और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या सरकार अफीम फैक्टरी की बेकार जमीन पर कोई फैक्टरी निर्माण करने का विचार कर रही है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा०) जकात :

(क) ११५ एकड़ ।

(ख) पोलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल के पास से सीधे कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया था । उत्तर प्रदेश के उद्योग निदेशक (हाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज) ने उत्तर प्रदेश सरकार की मार्फत केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की थी कि वह पोलिटेक्निक के विस्तार के लिए, गाजीपुर अफीम डिबीजन की बेकार भूमि और इमारतें उक्त संस्था को दे दे ।

(ग) जितने एकड़ भूमि मांगी गयी थी उसका विवरण इस प्रकार है :

(१) कार्यालय भवन और गोदाम २८२२६.८८ वर्गफुट

(२) भवन के साथ छोड़ी जाने वाली भूमि ६.३७ एकड़

राज्य सरकार को भूमि तथा इमारतें सौंप देने की बात को अन्तिम रूप दिया ही जाने वाला था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, गाजीपुर के जिला इंजीनियर ने गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट और कलक्टर को यह सुझाव दिया कि टूटी फटी दशा में होने के कारण ये इमारतें पोलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के लिए न ली जायं । गाजीपुर के कलक्टर ने यह सुझाव प्रवचय रखा कि राज्य सरकार इन इमारतों को केवल इस शर्त पर खरीद सकती है कि केन्द्रीय सरकार इनकी कोई कीमत न मांगे क्योंकि, उनके विचार से, ये इमारतें, टूटी फटी होने के कारण, बोज़ ही अधिक है । गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट और कलक्टर का यह सुझाव स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इमारतों की कोई कीमत लिये बिना ही इन इमारतों और भूमि का हस्तांतरण कर दिया जाय, क्योंकि केन्द्रीय सरकार की इमारतों को, मूल्य लिये बिना किसी राज्य को दे देने की अनुमति नहीं है ।

(घ) नहीं । उस बेकार भूमि पर कोई कारखाना खोलने का केन्द्रीय सरकार का विचार नहीं है ।

श्री सरजू पाण्डे : वहां पर जो जमीन है, क्या केन्द्रीय सरकार ने उसमें से कुछ हिस्सा पोलिटेकनिक इंस्टीट्यूट के लिये दे दिया है ?

श्री ब० रा० अगत : मकान के साथ जो जमीन है वह पोलिटेकनिक इंस्टीट्यूट को किराये पर दे दी गई है ।

श्री सरजू पाण्डे : जो जमीन वहां पर थी, उस में से सरकार ने कोई प्लॉट दिया है या नहीं ?

उपस्थित महोदय : कहा तो गया है कि एक हिस्सा दे दिया गया है ।

श्री ब० रा० अगत : मकान के साथ जो जमीन थी वह दी गई है, भलग कोई जमीन नहीं दी गई ।

श्री सरजू पाण्डे : उसका मुआवजा अभी लगाया नहीं ?

**Mr. Deputy-Speaker:** Has compensation been assessed?

श्री ब० रा० अगत : कम्पेन्सेशन किस लिए ? इस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता ।

#### National Council of Applied Economics Research

\*916. { **Shri Shree Narayan Das:**  
**Shri Radha Raman:**

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the National Council of Applied Economics Research has submitted any suggestions and recommendations to Government as a result of a detailed study of the impact of India's tax structure on present and potential foreign investments;

(b) if so, whether a copy of such recommendations will be placed on the Table;

(c) whether these have been examined;

(d) if so, the nature of the reaction of Government; and

(e) whether any, and if so, which of the recommendations are proposed to be implemented by Government?

**The Deputy Minister of Finance (Shri B. R. Bhagat):** (a) and (b). The National Council of Applied Economic Research has forwarded to Government copy of its Study of Taxation Laws in India in relation to foreign investments. Its recommendations have been summarised in pages 154 to 157 and an extract thereof is laid on the Table of the Lok Sabha [See Appendix III, annexure No. 95].

(c) to (e). These recommendations will doubtless form part of the considerations that Government will bear in mind when reviewing fiscal policy from time to time.

**Shri Shree Narayan Das:** May I know whether, in order to implement some of the suggestions which would be acceptable to the Government, any legislation will be put forward in this House during this session?

**The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari):** We have not yet examined these suggestions I do not know if they are going to be accepted by the Government at all.

**Shri Shree Narayan Das:** May I know whether it is a fact that some suggestion with regard to this question has already been offered by the delegation which just went to the European countries and whether this suggestion could also be considered by the Government?

**Shri T. T. Krishnamachari:** I have seen in the newspapers that the delegation which went abroad has made certain suggestions. I have not seen those suggestions yet. Naturally all suggestions made by responsible organisations will be taken into consideration at the appropriate time if such a time does occur.